मेहनतकशों का पैग़ाम
Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

नेट पर उपलब्ध :
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

फटा पोस्टर निकला राहुल लेकिन बहुत देर से
गैर–मान्यता–प्राप्त स्कूलों की सीलिंग — 3

बेटी–हंता पिताओं को भी मुक्ति चाहिए
एक ही थैली के चट्टे–बट्टे हैं मोदी और आडवाणी — 4

शिक्षा का निजीकरण, सरकार, पूंजीपति और छात्र — 6

रुपये को 'मजबूत' बनाने की फ़िर साजिश!
विकास कार्यों के लिये सरकारी अनुदान जरूरी? — 8

वर्ष 26 अंक 22 फरीदाबाद, मंगलवार, 1-15 अक्टूबर 2013 फोन : - 9999595632 सहयोग राशि 2 रुपया

ई एस आई अस्पताल की मुक्ति

बहुत कठिन थी राह

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 13 सितम्बर को हरियाणा सरकार द्वारा तीन नम्बर स्थित ई एस आई अस्पताल को मुक्त करने सम्बन्धी पत्र जारी करने के बावजूद 28 सितम्बर को कहीं जाकर इसकी प्रक्रिया सम्पन्न हो पाई। पाठकों ने गतांक में पढ़ा होगा कि कितनी मुश्किल से इस प्रक्रिया की फ़ाइल हरियाणा सरकार के दफ़तरों से निकल पाई थी।

हरियाणा सरकार की एक टीम ने 16 तारीख को अस्पताल का दौरा करके चिट्ठी जारी की। उसे लेकर चिकित्सा विश्वविद्यालय रोहतक जाना पड़ा। फ़िर वहां से एक टीम आई। उसकी रिपोर्ट लेने फ़िर से 27 तारीख को रोहतक जाना पड़ा। उस रिपोर्ट को दिल्ली स्थित ई एस आई मुख्यालय भेजा गया। इसके बाद 28 तारीख को ई एस आई निगम ने इस अस्पताल का विधिवत कब्ज़ा लिया।

कब्ज़ा लेने की औपचारिकता इसी शहर के सेक्टर 16 में बैठे क्षेत्रीय निदेशक को पूरी करनी थी। इसे पूरा करने में मानो उनकी जान निकल रही थी। दिल्ली स्थित मुख्यालय से फटकार पड़ने के बाद बड़ा रो-पीट कर निदेशक ने हस्ताक्षर किये। ये सारी औपचारिकतायें पूरी होने के बाद ही एम सी आई (भारतीय चिकित्सा परिषद) में मेडिकल कॉलेज खोलने सम्बन्धी अर्जी लगनी है जिसकी अन्तिम तारीख 30 सितम्बर है।

जैसा कि गतांक में पाठकों ने पढ़ा था कि निहित स्वार्थों के चलते राज्य सरकार के सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों को इस हस्तांतरण से बड़ी भारी तकलीफ़ हो रही थी। वैसी ही तकलीफ़ ई एस आई के क्षेत्रीय निदेशक तथा उसके कुछ अफ़सरों को भी हो रही थी, जिसकी वजह से वे इस प्रक्रिया में यथासंभव रोड़े अटकाने का प्रयास आखरी क्षण तक करते रहे।

ई एस आई निगम ने अस्पताल का कब्ज़ा तो रो-पीटकर ले लिया लेकिन आज के दिन अस्पताल में मात्र 17 डाक्टरों सहित नाम मात्र ही स्टाफ़ मौजूद है। जो स्टाफ़ ई एस आई निगम की नौकरी की अपेक्षा हरियाणा सरकार की ही नौकरी में रहना चाहते हैं, वे अस्पताल को छोड़ कर अन्यत्र जा चुके हैं।

शेष पेज 2 पर

भाग मोदी भाग, ताकि मैं जीतूं

सभी जानते थे, कि(राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ)के बुलडोज़र के आगे आडवाणी का 'लोहा' पिसना ही है। 'लौहपुरुष' लाख रोये-रूठे पर आर एस एस ने नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करा दिया। सब यह भी जानते थे कि कुछ ही समय में आडवाणी भी पार्टी की उसी लाइन में खड़े नज़र आयेंगे जिसमें मोदी की जयजयकार हो रही है। हुआ भी वही। चलो, बेशर्म तो हैं आडवाणी पर शातिर भी कम नहीं।

बेशर्म शातिर

अगर आडवाणी आज मोदी की जयकारे में शामिल नहीं होते तो आर एस एस ने उन्हें बलराज मधोक की तरह राजनीति के कूड़ेदान में फेंक दिया होता। क्योंकि भाजपाईयों को भी सत्ता में पहुंचने की मोदी सीढी पर ही भरोसा जम चुका है, लिहाज़ा शायद ही कोई आडवाणी के हाल पर आंसू बहाता। कोपभवन में बैठा आडवाणी न केवल राजनैतिक वनवास की नियति ही भुगतता बल्कि वह हमेशा के लिये अपने प्रधानमंत्री बनने के सपने से भी हाथ धो बैठता।

मोदी के समर्थन में आवाज़ देकर आडवाणी ने अब भी एक भ्रामक छवि और एक महीन आशा ज़िंदा रखी है। छवि, कि वह सत्ता की दावेदार भाजपा का कद्दावर नेता है। आशा, कि कहीं चुनाव के बाद सहयोगी दलों ने मोदी को स्वीकार न करने की ज़िद पकड़ ली तो उसकी लॉटरी फ़िर खुल सकती है।

हुड्डा भी चौटाला की राह पर

पुलिस भर्ती के लिये अपने प्यादों का बोर्ड बना कर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा उसी राह पर अग्रसर हैं। जिस पर चलकर औमप्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल में पहुंच गये हैं। भर्ती बोर्ड के सदस्यों के नामों पर नज़र डालने से ही समझ में आ जाता है कि सफ़ल उम्मीदवारों की लिस्टें हुड्डा साहब के कैम्प ऑफिस में ही बनेंगी। यह भी जाहिर है कि इस पूरी कवायदा में मुख्यमंत्री के बेटे दीपेन्द्र सिंह हुड्डा की भी शिरकत रहेगी। चौटाला साहब का तिहाड़ जेल में उनके साहबज़ादे अजय साथ दे रहे हैं। यदि हुड्डा के बनाये बोर्ड ने भर्तियां सम्पन्न कर दीं तो पूरे आसार हैं कि पिता का साथ दीपेन्द्र हुड्डा भी जरूर देंगे।

भर्ती घोटालों में जुटे हुड्डा

11000 सिपाहियों के भर्ती के लिये बनाये गये बोर्ड में ये लोग हैं। ब्रिगेडियर जे एस मान, ओपी लोहान, राहुल राव, प्रदीप जैलदार, राजेन्द्र बला, जसवंत सिंह खैरा, बलराज सिंह। ये सभी भूपेन्द्र और दीपेन्द्र से करीबी रूप से जुड़े हुए लोग हैं। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अभी तक पुलिस भर्ती लिस्टें बनवाने में सक्रिय, मुख्यमंत्री के पुलिस सलाहकार परमवीर राठी की बोर्ड बनने के बाद क्या भूमिका रहेगी।

हरियाणा में फ़र्जी पुलिस की भर्ती कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद राज्य के सीआईडी दफ़्तर में पेंसिल से बनाई सिफारिशी लिस्टें एवं पैसा चढाने वालों के नाम फ़ाइनल करके उन पर सम्बन्धित एसपी की मुहर लगवाने की परम्परा राज्य में भजन लाल के राज से चली आ रही है।

– शेष पेज 2 पर

ख़बर दार

समस्या बार्डर या दिल्ली नहीं, समस्या स्वयं मोदी है

प्रधानमंत्री पद के लिये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भाजपाई ट्रोज़न घोड़े नरेन्द्र मोदी ने स्वयं को लौह-पुरुष दिखाने की ठान रखी है। उनके भूत या वर्तमान में तो कोई साहसिक कारनामा है नहीं,सिवाय अपने वफादार साथियों को करारा गच्चा देने का लिहाज़ा अपनी उम्मीदवारी की घोषणा होते ही उन्होंने पहली रैली रेवाड़ी में भूतपूर्व सैनिकों की कर डाली। बगल में सेवानिवृत जनरल वीके सिंह को बिठा लिया और इस 'मजबूत' मंच से स्वयं को 'मजबूत' सिद्ध करने में लग गये।

भूतपूर्व सैनिकों की भीड़ से तालियां बजवाने के लिये मोदी ने अजमाये हुए

नारे, ''एक रैंक एक पेंशन'' का सहारा लिया।

मोदी ने यह वायदा तो किया कि वे प्रधानमंत्री बन कर इस दशकों से लम्बित योजना को साकार करेंगे पर यह बताना जरूरी नहीं समझा कि जब केन्द्र में भी भाजपाई सरकार थी तो इसे लागू क्यों नहीं किया गया? इसी तरह मोदी ने जवानों की बहादुरी के गुणगान तो खूब किये पर बिना लेश मात्र भी बताये कि कैसे उन्हीं जवानों को उनके अपने ही अफ़सरों द्वारा कल्याण-योजनाओं की मार्फ़त लूटा जाता है। ऐन उसी दिन जब मोदी की रिवाड़ी रैली चल रही थी, भूतपूर्व सैनिकों को छलपूर्वक हज़ारों करोड़ के रोज़गार स्कैम में मोहरा बनाने वाले सेना के वरिष्ठ सेवारत एवं सेवानिवृत अधिकारियों के षडयंत्र का भांडा मीडिया में फूटा था। जाहिर है, मोदी को भी दूसरे शासकों की तरह दोस्तियां सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से निभानी हैं, न कि आम जवानों से।

– शेष पेज 2 पर

क्या–क्या फेंकोगे कूड़ेदान में?

27 सितम्बर को राहुल गांधी ने कहा कि राजनीतिज्ञों को पहली सज़ा पर चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करले वाला मनमोहन सरकार का अध्यादेश कूड़ेदान में फ़ेंकने के योग्य है। सवाल यह है कि मनमोहन सरकार में ऐसा क्या है जो कूड़ेदान में फ़ेंकने योग्य नहीं हैं उसकी नितियां, उसके मंत्री, उसके स्कैम, उसकी सत्तारूढ़ रहने की तिकड़में, उसका भ्रष्टाचार, उसके मन्त्री, उसके दलाल, उसके सलाहकार इतयादि। इस देश की जनता पर एक परजीवी बोझा ही तो हैं। यह बोझा जितनी जल्दी कूड़ेदान में फ़ेक दिया जाय उतना अच्छा।

29 सितम्बर को नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली की चुनावी सभा में समूचे गांधी परिवार को जिस तरह पानी पी-पी कर गालियां दी उसका सार भी यही था कि सारा गांधी-परिवार उस अवस्था को प्राप्त कर गया है कि उसे राजनीति के कूड़ेदान में ही जगह मिलनी चाहिए। राहुल की तरह ही मोदी भी यह बताना जरूरी नहीं समझे कि उनके अपने गुलदस्ते में कौन सी फूल हैं जो इस देश के वातावरण को ईमानदारी और सच्चाई की महक से भर देंगे।